

भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय संबंध

(भारतवर्ष व नेपाल का एक प्रक्रियात्मक (आचारपरक) भौगोलिक विश्लेषण)

डॉ० सर्वेश्वर नाथ सिंह एसो० प्रोफेसर
भूगोल, एम० एल० के० (पी०जी०) कालेज
बलरामपुर (उ०प्र०)

“नेपाल व नाथ पंथ एक-दूसरे में ऐसे रचे-बसे हैं कि चाह कर भी एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकते। कभी-कभी शासक वर्ग भले चीन की भाषा बोलने लगे किन्तु नेपाल की जनता हमेशा भारत के स्वर में ही स्वर मिलाकर बोलती है। इसका एक विशिष्ट उदाहरण गोरखा सैनिक है जो भारतीय सेना का एक गौरवशाली हिस्सा हैं जो भारत के लिए जीते-मरते हैं।”

नेपाल, भारत और चीन के मध्य स्थित है जहां पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। विश्व की 14 सबसे उच्च चोटियों में 8 यहीं पर हैं। जिसका क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किमी० है। जिसकी जनसंख्या 3 करोड़ है।

पड़ोसी राष्ट्र नेपाल पूर्णतया स्थल से घिरा है। भारत की लगभग 1860 किमी० सीमा नेपाल से सटी है। हिमालय की गोद में बसे नेपाल की उत्तरी सीमा तिब्बत से मिलती है तथा इसकी पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमायें भारत से मिलती हैं। नेपाल चारों तरफ से विशाल देशों से भूबद्ध (Landlock) देश है।

अध्ययन विधि तंत्र-

प्रस्तुत शोध-प्रपत्र का विधि तंत्र द्वितीयक आकड़ों पर आधारित है, अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने हेतु विविध सांख्यिकीय विधियों का उपयोग किया गया है। अध्ययन का विधि तंत्र विश्लेषणात्मक है।

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य भारत-नेपाल के अंतरराष्ट्रीय संबंधों का ऐतिहासिक, वर्तमान व भविष्य के अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण करना है।

भारत-नेपाल संबंधों की पृष्ठभूमि-

सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों के कारण नेपाल हमारी विदेश नीति में भी विशेष महत्व रखता है। भारत और नेपाल हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म के संदर्भ में समान संबंध रखते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान लुंबिनी नेपाल में है और जबकि उनका निर्वाण स्थान कुशीनगर भारत में स्थित है। वर्ष 1950 की भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि दोनों देशों के बीच मौजूदा विशेष संबंधों का आधार है।

सन् 1951 में नेपाल नरेश व नेपाली कांग्रेस के बीच समझौता हुआ तथा प्रथम बार संसद हेतु चुनाव हुए तथा नेपाली कांग्रेस के वी० पी० कोइराला के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्षरत नेपाली कांग्रेस के प्रायः वरिष्ठ नेताओं की शिक्षा - दीक्षा भारत में हुई। इन नेताओं ने अपने देश में निरंकुश राजाशाही का अन्त कराया। 30 जुलाई 1950 को भारत में नेपाल के मध्य "भारत - नेपाल शान्ति व सहयोग" की एक सन्धि हुई। न तो 1947 से पूर्व और न ही इसके बाद ब्रिटेन अथवा भारत ने नेपाल के आन्तरिक मामलों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। भारत के प्रयास से नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। 13 अगस्त, 1971 को दोनों देशों के बीच एक पंचवर्षीय समझौता किया गया जिसके तहत भारत ने नेपाल के कच्चे माल के व्यापार की खुली छूट दे दी एवं उसे मार्ग सुविधायें भी प्रदान कर दी।

भारत ने नेपाल की पंचवर्षीय योजनाओं में भरपूर सहायता दी है तथा उसकी आर्थिक दशा को सुधारने हेतु भी उदारता से ऋण दिया है। भारत नेपाल को कोलकाता बंदरगाह को उपयोग में लाने हेतु अनुमति प्रदान की गई। कोसी तथा त्रिशूली परियोजनाओं में भारत ने उदारता से अपार धनराशि खर्च की तथा भारत ने अनेक सड़कों का निर्माण किया। भारत ने नेपाल को आर्थिक सहयोग दिया तथा उसने

नेपाल की बड़ी-बड़ी नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई एवं बिजली पैदा करने वाली अनेक परियोजनाओं को पूरा करके उसे तथा स्वयं को लाभांवित किया है।

नेपाल जलीय संसाधनों में एक धनी देश है। यदि दोनों देश इस क्षेत्र में निकटतम सहयोग करें तो इससे न केवल नेपाल का कायापलट हो सकता है अपितु भारत की अतृप्ति ऊर्जा अर्थव्यवस्था को भी सम्बल प्राप्त हो सकता है। दोनों देश आज तक सिंचाई, विद्युत, बाढ़ नियंत्रण तथा इसी प्रकार के आपसी लाभप्रद आर्थिक परियोजनाओं से वंचित रहे हैं। नेपाल में कृषि उत्पादन, सीमेंट और ऊर्जा के उत्पादन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

नेपाल और भारत दुनिया के दो प्रमुख धर्मो-हिंदू और बौद्ध धर्म के विकास के आसपास एक सांस्कृतिक इतिहास साझा करते हैं। बुद्ध ज्ञान की खोज में वर्तमान भारतीय क्षेत्र बोधगया आए, जहाँ उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। बोधगया से महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों ने विश्व के कोने-कोने तक बौद्ध धर्म का प्रसार किया। भारत व नेपाल दोनों ही देशों में हिंदू व बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। रामायण सर्किट की योजना दोनों देशों के मजबूत सांस्कृतिक व धार्मिक संबंधों का प्रतीक है। भारत-नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों के संबंधों की विशिष्टता है, जिससे दोनों देशों के लोगों को आवागमन में सुगमता रहती है। दोनों देशों के नागरिकों के बीच आजीविका के साथ-साथ विवाह और पारिवारिक जन-जीवन संबंधों की मजबूत नींव है। इस नींव को ही 'रोटी-बेटी का रिश्ता' नाम दिया गया है। भारत, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार होने के साथ-साथ विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत, नेपाल को अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिये पारगमन सुविधा भी प्रदान करता है। नेपाल अपने समुद्री व्यापार के लिये कोलकाता बंदरगाह का उपयोग करता है। भारतीय कंपनियाँ नेपाल में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं। इन कंपनियों की नेपाल में विनिर्माण, बिजली, पर्यटन और सेवा क्षेत्र में उपस्थिति है। भारत सरकार नेपाल में जमीनी स्तर पर बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए समय-समय पर विकास सहायता प्रदान करती है। इसमें बुनियादी ढाँचे में स्वास्थ्य, जल संसाधन,

शिक्षा, ग्रामीण और सामुदायिक विकास जैसे मुद्दे शामिल हैं। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के तहत उपकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से नेपाल की सेना का आधुनिकीकरण शामिल है। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट्स में नेपाल के पहाड़ी इलाकों से भी युवाओं की भर्ती की जाती है। भारत वर्ष 2011 से नेपाल के साथ प्रति वर्ष 'सूर्य किरण' नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास करता आ रहा है। नेपाल में अक्सर भूकंप, भू-स्खलन और हिमस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा रहता है। ऐसा मुख्य रूप से भौगोलिक कारकों के कारण होता है क्योंकि नेपाल एक प्राकृतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है। भारत आपदा से संबंधित ऐसे किसी भी मामले में कर्मियों की सहायता के साथ-साथ तकनीकी और मानवीय सहायता भी प्रदान करता रहा है। भारत-नेपाल ने अपने नागरिकों के मध्य संपर्क बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न कनेक्टिविटी कार्यक्रम शुरू किये हैं। हाल ही में भारत के रक्सौल को काठमांडू से जोड़ने के लिये इलेक्ट्रिक रेलट्रैक बिछाने हेतु दोनों सरकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

नेपाल, भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों के कारण वह हमारी विदेश नीति में भी विशेष महत्व रखता है।

विश्वस्त सूत्रों के अनुसार नेपाल के राज्य दांग के राजकुमार जो कालान्तर में योगी रतन नाथ, नाथ पंथ के बहुत सिद्ध योगी हुये, देवीपाटन शक्तिपीठ तुलसीपुर, बलरामपुर (उ० प्र०) अर्चना, भाव-भगत हेतु वे प्रतिदिन दांग चौखड़ा (नेपाल) से आया करते थे आज भी प्रतिवर्ष वहाँ से पैदल ही शोभायात्रा आती है। वस्तुतः नाथ पंथ की परंपरा बेहद समृद्ध है जो तिब्बत से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका तक को एक सूत्र में जोड़ता है।

गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही 15 वी शताब्दी में द्रव्यशाह ने नेपाल में शाह राजवंश की स्थापना की और पृथ्वीनारायण शाह ने विभिन्न भूखंडों में बंटे नेपाल

का एकीकरण कर एक सम्प्रभु राष्ट्र की नींव डाली। बीच में दो सौ वर्षों तक राणा वंश ने भी नेपाल में शासन किया लेकिन भारत की आजादी के बाद भारत सरकार ने तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ के सहयोग से महाराजाधिराज त्रिभुवन को नेपाल के शासक के रूप में मान्यता दी। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली अपनाने और हिन्दू राष्ट्र से विमुख होने तक नेपाल में इसी वंश का शासन था। इन तमाम उतार - चढ़ावों के बावजूद आज भी नेपाल शाही परिवार, मृगस्थली के महंत और बड़ी संख्या में नेपाल के नागरिकों की खिचड़ी गोरखनाथ मंदिर में चढ़ती है। नेपाल शाही परिवार गुरु गोरखनाथ को अपनाराजगुरु मानता है। नेपाल व नाथ पंथ एक-दूसरे में ऐसे रचे-बसे हैं कि चाह कर भी एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकते। कभी-कभी शासक वर्ग भले चीन की भाषा बोलने लगे किन्तु नेपाल की जनता हमेशा भारत के स्वर में ही स्वर मिलाकर बोलती है। इसका एक विशिष्ट उदाहरण गोरखा सैनिक है जो भारतीय सेना का एक गौरवशाली हिस्सा हैं जो भारत के लिए जीते-मरते हैं।

भारत - नेपाल विवाद मुख्य रूप से व्यापार और पारगमन सन्धियों को लेकर प्रारम्भ हुआ। यह सही है कि दोनों देशों के बीच अक्टूबर, 1988 में व्यापार सन्धि पर प्रारम्भिक हस्ताक्षर हो गये थे। भारत को यह आशा थी कि भारतीय सामानों पर नेपाल द्वारा लगाया गया भारी सीमा शुल्क स्वतः समाप्त हो जायेगा। परन्तु ऐसा नहीं किया जा सका। दूसरी ओर नेपाल ने सड़क से आने वाले चीन के माल पर साठ प्रतिशत की छूट दे दी। अतः प्राथमिकता का वादा करके भारत के साथ वादा खिलाफी की गई। इसके अतिरिक्त भारत व्यापार और पारगमन दोनों के लिए संधि चाहता है जबकि नेपाल अलग-अलग संधि चाहता है। नेपाल ने अप्रैल, 1987 में आंशिक तौर से तथा सितम्बर, 1988 से पूरे देश में भारतीय मूल के लोगों के लिए रोजगार परमिट अनिवार्य कर दिया जबकि भारत ने 1950 की सन्धि का अनुपालन करते हुए ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। भारत में लगभग 35 लाख नेपाली रहते हैं। तथा नेपाल में 50,000 भारतीय रहते हैं। सन् 1950 की सन्धि के ही कारण उनका पंजीकरण नहीं किया गया है। यह सर्वविदित है कि भारत-नेपाल व्यापार का सबसे भयावह पहलू है

तस्करी|नेपाल के पर्याप्त सहयोग न देने के कारण भारत को सर्वाधिक हानि होती है । अतः भारत को फूंक-फूंक कर कदम उठाना होगा ।

भारत-नेपाल के मध्य कुछ विवाद-

भारत व नेपाल के मध्य हालिया विवाद का कारण उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ती एक सड़क है । नेपाल का दावा है कि कालापानी के पास पड़ने वाला यह क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है और भारत ने नेपाल से वार्ता किये बिना इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य किया है । नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल का नवीन मानचित्र जारी किया गया, जो उत्तराखंड के कालापानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है । नेपाल ने इस संबंध में वर्ष 1816 में हुई सुगौली संधि का जिक्र किया है ।

हाल ही में भारत के लिए स्थिति उस समय सहज हो गई जब कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत द्वारा लिपुलेख-धारचूला मार्ग के उद्घाटन करने के बाद नेपाल ने इसे एक तरफा गतिविधि बताते हुए आपत्ति जताई । नेपाल के विदेश मंत्रालय ने यह दावा किया कि महाकाली नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल की सीमा में आता है । विदित है कि नेपाल ने आधिकारिक रूप से नवीन मानचित्र जारी किया गया, जो उत्तराखंड के कालापानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है । निश्चित रूप से नेपाल के इस प्रकार की प्रतिक्रिया ने भारत को अचंभित कर दिया है । इतना ही नहीं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल में कोरोना वायरस के प्रसार में भारत को दोष देकर दोनों देश के बीच संबंधों को तनावपूर्ण कर दिया । वस्तुतः इसे चीनी जादू कहा जाए या नेपाल की कूटनीतिक चाल कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार भारत को परेशान करने की कोशिश हो रही है । भारत इन सभी कोशिशों को नेपाल की चीन से बढ़ती नजदीकी के रूप में देख रहा है । ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने रिश्ते पर चीनी चाल भारी पड़ रही है ?

भविष्य की योजना-

नेपाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह दो देशों के मध्य घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों की भावना को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक संधि, दस्तावेजों, तथ्यों और नक्शों के आधार पर सीमा के मुद्दों का कूटनीतिक हल प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है। भारत को भी अपनी विदेश नीति की समीक्षा करने की भी जरूरत है। भारत को नेपाल के प्रति अपनी नीति दूरदर्शी बनानी होगी। जिस तरह से नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, उससे भारत को अपने पड़ोस में आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करने से पहले रणनीतिक लाभ-हानि पर विचार करना होगा। भारत और चीन के साथ नेपाल एक आज़ाद सौदागर की तरह व्यवहार कर रहा है और चीनी निवेश के सामने भारत की चमक फीकी पड़ रही है। लिहाज़ा, भारत को कूटनीतिक सुझबूझ का परिचय देना होगा।

यह भारत और नेपाल के मध्य द्विपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के बीच घनिष्ठ रणनीतिक संबंध स्थापित करना है। यह संधि दोनों देशों के बीच लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही और रक्षा एवं विदेशी मामलों के बीच घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग की अनुमति देती है। साथ ही यह संधि नेपाल को भारत से हथियार खरीदने की सुविधा भी देती है। इस संधि के द्वारा नेपाल को एक भू-आबद्ध (Land-lock) देश होने के कारण कई विशेषाधिकारों को प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। भारत-नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों के संबंधों की विशिष्टता है, जिससे दोनों देशों के लोगों को आवागमन में सुगमता रहती है। दोनों देशों के बीच 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी साझा सीमा है, जिससे भारत के पाँच राज्य-सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड जुड़े हैं। भारत और नेपाल के बीच सीमा को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं है। लगभग 98% प्रतिशत सीमा की पहचान व उसके नक्शे पर सहमति बन चुकी है, कुछ क्षेत्रों को लेकर विवाद है जिसे बातचीत के माध्यम से सुलझाने की प्रक्रिया चल रही है।

वस्तुतः भारत-नेपाल की सीमा व विविध समस्याओं के समाधान में गोरक्षनाथ मंदिर की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि नेपाली जन-जीनव मे गुरु गोरक्षनाथ विद्यमान हैं जो विषम परिस्थितियों मे भी लंबे समय के लिए एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकते ।

संदर्भ-

1. जगदीश सिंह (2013) : भौगोलिक चिंतन के मूलाधार , ज्ञानोदय प्रकाशन गोरखपुर ।
2. शाह, ऋषिकेश (1992) : प्राचीन और मध्यकालीन नेपाल , रत्न पुस्तक भंडार काठमांडू ।
3. सिंह कन्हैया : गोरखनाथ जीवन दर्शन राजकमल प्रकाशन , दरियागंज नई दिल्ली ।
4. द्विवेदी हजारी प्रसाद : नाथ सिद्धों की रचनाएं , राजकमल प्रकाशन प्रयागराज ।

